(ग) क्या यह भी सच है कि हमारे देश में इस्पात के उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी अन्य प्रतिस्पर्द्धी देशों में उपयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी से भिन्न है;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में इस्पात के उत्पादन की प्रौद्योगिकी भू.पू. सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित की गई थी जो महंगी साबित हो रही है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा अनेकों कर और उपकर लगाए गए हैं ताकि हमारे देश के इस्पात का मूल्य अन्य देशों के इस्पात के मूल्य के बराबर हो सके; और

(च) यदि हां, तो गत वर्षों में इस्पात की उत्पादन लागत में कमी लाने के प्रयास न किए जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) अन्य देशों में इस्पात की उत्पादन लागत से संबंधित किसी प्रमाणित सूचना के उपलब्ध न होने से भारत में इस्पात के उत्पादन की लागत की अन्य देशों में इस्पात के उत्पादन की लागत से तुलना करना संभव नहीं है।

(ख) देश में अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन वर्ष 1951 में लगभग 15 लाख टन था जो 1992-93 में बढ़कर लगभग 181.6 लाख टन हो गया।

(ग) विकसित देशों में इस्पात संयंत्र मुख्यतया बेसिक आक्सीजन फर्नेस और सतत ढलाई प्रौद्योगिकी में परिवर्तित हो गए, जबकि भारत में अधिकांश पुराने एकीकृत इस्पात संयंत्र अभी भी ओपन हर्थ फर्नेस/ट्विन हर्थ फर्नेस और पिंड ढलाई पद्धति का भिन्न-भिन्न मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। ऐसे इस्पात संयंत्रों द्वारा प्रौद्योगिकीय उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं।

(घ) स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्र विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र (वी.एस.पी. तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किए गए थे। विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र में हाल ही में उत्पादन शुरू हो गया है। तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित सेल के संयंत्रों द्वारा उत्पादित इस्पात के उत्पादन की लागत की तुलना अन्य विकसित देशों की उत्पादन लागत से नहीं की जा सकती, क्योंकि उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी, आदानों के मूल्य, उत्पाद-मिश्र तथा सांविधिक लेवियों आदि की मात्रा में अन्तर है।

(ङ) विभिन्न देशों में इस्पात के मूल्यों में अन्तर होता है तथा एक ही देश में विभिन्न उत्पादकों के मूल्यों में भी अन्तर रहता है। सरकार द्वारा कर आदि विभिन्न प्रयोजनों के लिए लगाए जाते हैं न कि इस्पात के मूल्यों को अन्य देशों के मूल्यों के बराबर करने के लिए।

(च) इस्पात की उत्पादन लागत में कमी करने के लिए सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस्पात की उत्पादन लागत में कमी करने के लिए संयंत्रों का आधुनिकीकरण, तकनीकी-आर्थिक प्राचलों में सुधार जो उत्पादन की वर्धित क्षमता को प्रभावित करता है, उत्पाद-मिश्र का विविधीकरण, पुनःप्रशिक्षण और पुनः तैनाती सहित श्रम-शक्ति को युक्तिसंगत करना, दूसरे खर्चों सहित ऊर्जा खपत और पेट्रोल ईंधन खपत में कमी करने जैसे अनेक कदम उठाए जा रहे हैं।

Commercialisation of Residential Houses

2138. SHRIMATI SARALA MAHESHWARI : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have announced the commercialisation of the residential houses on the main roads, having 80 ft. wide road, and if so, the reasons therefor;

(b) whether it is also a fact that the houses on the main road of Aurobindo Marg specially in Green Park and Malviya Nagar, New Delhi are also covered under the above mentioned scheme;

(c) if so, the details thereof and by when this scheme is likely to be implemented; and

(d) what are formalities for this scheme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Question does not arise.

Financing Transport Related Projects

2139. SHRI P. UPENDRA : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the question of financing transport-related projects in the National Capital Region of Delhi was discussed at a meeting organised by the Delhi Traffic and Transport Group recently;

(b) what are the suggestions given by the Group; and

(c) what is the reaction of Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Managing our Metropolies

2140. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government had taken note of the recommendations made by Experts in a symposium on "Managing our metropolies" organised by National Institute of Urban Affairs, National Institute of Public Finance and Policy and the Indian Institute of Public Administration stressing need for "reforms in land planning"; and

(b) if so, what is the reaction of the Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) and (b) No, Sir. The Symposium was organised by the School of Planning and Architecture, New Delhi in March. 1993, with other agencies like NIUA etc. as co-sponsors. The final recommendations of the Symposium have not been received in the Ministry.

Construction of Toli-way-Bridge over Yamuna

2141. SHRI N. E. BALARAM : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Memorandum of Understanding was signed with NOIDA and Delhi Administration by M|s. Infrastructure Leasing and Financial Services Ltd. (IL&FS) for the construction of a Toli-way Bridge over Yamuna for easier movement of NOIDA population to South Delhi via Maharani Bagh;

(b) whether it is a fact that IL&FS also set up a Steering Committee to monitor the progress and implementation of the above said project; and

(c) if so, what is the latest position in regard to (b) above and the total amount sanctioned and released by the authorities concerned for the said project on a particular date and target date, if any for the completion of the Project ?